Tc.No.: GUJHIN00722

दैनिक

क्रांति समय

E-mail: krantisamay@gmail.com

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 32, शनिवार, 24 फरवरी 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

सार समाचार

कन्नौजः डीजल भरवाते समय अचनाक स्टार्ट हो गई कार

कन्नौज (एजेंसी)। सरायमीरा-कन्नौज रोड पर बोर्डिंग ग्राउंड के सामने सतीश फिलिंग स्टेशन पर लाल रंग की एक कार डीजल डलवाने के लिए रुकी। कार चालक मोबाइल फोन पर बात करते हुए टहलने लगा। जबकि कार में 3 अन्य युवक भी सवार थे। डीजल पड़ने के बाद कार में सवार एक अन्य युवक ने कार को स्टार्ट कर दिया। अचानक कार चल पड़ी और युवक उसे संभाल नहीं पाया। कार सामने खड़े बाइक सवार और पम्प कर्मी को टक्करते हुए पंप का चक्काकर काटने लगी। इस दौरान पंप पर भगदड़ मच गई। कार अचानकर पंप की दीवर को टक्कर मारते हुए रुक गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तब तक कार के ड्राइवर की सीट पर बैठा युवक भाग निकला। उसके दो साथी भी भाग निकले। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। यहां से पुलिस ने कार में सवार एक अदनान नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है। मामले को लेकर पम्प मालिक की ओर से अनिल कुमार पांडेय ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। उधर, कार की टक्कर से घायल बाइक सवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सिसोदिया ने भेजा सचिवों को साप्ताहिक रिपोर्ट देने का निर्देश

नई दिल्ली। लगातार चल रहे विवाद के बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी विभागीय सचिवों को आदेश दिया कि ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (टीबीआर) के अनुसार वे अपने विभाग में सभी प्रकार की योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट उन्हें दें। सभी अफसरों ने मंत्री की बैठक में भाग लेना बंद कर दिया है जिसके बाद सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को यह आदेश जारी किया ताकि अधिकारियों को टीबीआर नियमों में बांधा जा सके।सिसोदिया ने सभी सचिवों को निर्देश दिया कि साप्ताहिक रिपोर्ट देने संबंधी आदेश 29 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। अब 26 फरवरी से सभी सचिव साप्ताहिक रिपोर्ट भेजेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव अपने विभाग के सभी प्रस्ताव व योजना की जानकारी देंगी। अगर शिक्षा विभाग का कोई काम अन्य विभाग में लंबित है तो रिपोर्ट में सिर्फ योजना के लंबित होने की जानकारी देना काफी नहीं होगा बल्कि उस विभाग से पूरी जानकारी प्राप्त करना होगा व उस जानकारी को पेश करना होगा। योजना क्यों लंबित है यह भी सचिव को बताना होगा। सिसोदिया ने पत्र में लिखा है कि यदि कोई बड़ी परियोजना एक महीने से ज्यादा लंबित हो चुकी है तो उसे कई भागों में विभक्त कर उसके प्रत्येक हिस्से का टाइमलाइन तय करना होगा। टीबीआर में प्रत्येक विभागीय सचिव को प्रत्येक सप्ताह सोमवार को अपने विभाग के पिछले सप्ताह में हुए सभी कायरे व योजना की प्रगति संबंधी रिपोर्ट मंत्री को देने का प्रावधान किया गया है।

कई मंत्री नहीं पहुंचे कार्यालय

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के ज्यादातर मंत्री बृहस्पतिवार को कार्यालय नहीं पहुंचे। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुबह कार्यालय पहुंचे जबकि इमरान हुसैन दोपहर तक कार्यालय पहुंचे। शाम पांच बजे थोड़ी देर के लिए परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी कार्यालय आए लेकिन एक भी वरिष्ठ या कनिष्ठ अधिकारी मंत्री की बैठक में जाने को तैयार नहीं था। आईएएस, दानिक्स, दास व अन्य सभी एसोसिएशन ने मंत्री की बैठक में न जाने का फैसला ले लिया है जो मंत्रियों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है।

चोरी के माल के खरीदार सहित तीन बंदी

नई दिल्ली। बाहरी दिल्ली में सेंधमारी व चोरी की वारदातें करने वाले एक गैंग के दो बदमाशों गिरफ्तार कर पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की स्कूटी, 56 मोबाइल फोन व एक एलईडी टीवी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक दोनों से हुई पूछताछ के आधार पर चोरी का माल खरीदने वाले खरीददार को भी पकड़ लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेन्द्र सिंह सागर के मुताबिक 21 फरवरी को वाई ब्लॉक मंगोलपुरी 901 बस स्टैंड के नजदीक चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार दो संदिग्ध लोगों को रोक लिया और उनसे स्कूटी की कागजात दिखाने को कहा तो वह नहीं दिका सके। जांच-पड़ताल में पता चला कि स्कूटी विजय विहार इलाके से चुराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने सागर और देव कुमार दोनों का गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि वह मंगोलपरी और सुलतान पुरी क्षेत्र में चोरियां करते हैं और वारदात के बाद सामान संदीप को बेच देते हैं।

»» गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को 31 मार्च से बन्द करने के आदेश का विरोध

गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के खिलाफ संचालकों का प्रदर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के सरकारी आदेश के विरोध में स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में स्कूलों के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। सरकार ने दिल्ली के करीब 3000 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को 31 मार्च से बन्द करने का आदेश दिया है।सरकार के आदेश के विरुद्ध बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों व स्कूल संचालकों ने ट्रामा सेन्टर पर एकत्र होकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया। साथ ही ऐसे सभी स्कूल सरकार के आदेश के विरोध में बंद भी रखे गए। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स मैनेजमेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने बताया कि 1 अपैल 2010 से मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून 2009 की धारा 18 व 19 के अनुसार सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को कानून लागू होने के तीन वर्ष के अन्तर्गत मान्यता लेनी आवश्यक है अन्यथा उसके बाद स्कूल चलाने पर स्कूल संचालक पर एक लाख रपए का तुरन्त जुर्माना व प्रतिदिन 10 हजार रपए का जुर्माना ऐसे स्कूलों को भरना होगा।

जैन ने कहा कि जिस कानून में तीन वर्ष में मान्यता लेने का प्रावधान है उसी कानून की धारा 6 में साफ लिखा है कि सरकार 3 वर्ष के अन्दर हर बच्चे के पड़ोस में नए स्कूल बनाकर उस बच्चे के शिक्षा के अधिकार को पूरा करेगी। क्या सरकार मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून 2009 की इस धारा के अनुसार स्कूल नहीं बना पाई। पांच सौ नए स्कूल बनाने का दावा करने वाली सरकार 3000 स्कूलों को बन्द करने का आदेश देकर अपनी गरीब विरोधी नीति को उजागर कर रही है।

मैं इस देश की राजनीति का सबसे कम उम्र का आडवाणी : कुमार विश्वास

देश की राजनीति का सबसे कम उम्र का आडवाणी बताकर लोगों को खूब हंसाया। सन 2014 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके कवि व नेता कुमार विश्वास गुरुवार की शाम कवि सम्मेलन में शामिल होने अमेठी आए थे।

अमेठी। अमेठी के शिवदुलारी सिंह महिला महाविद्यालय गुंगवाछ में आयोजित कवि सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे आप नेता कुमार विश्वास ने देश के राजनीतिक माहौल पर जमकर चुटकी ली। उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष पर भी व्यंग्य बाण चलाए।

उन्होंने स्वयं को देश की राजनीति का सबसे कम उम्र का आडवाणी बताकर लोगों को खूब हंसाया। सन 2014 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके कवि व नेता कुमार विश्वास गुरुवार की शाम कवि सम्मेलन में शामिल होने अमेठी आए थे।

जहां माइक संभालते ही उन्होंने कहा कि आप लोगों को मेरा इसलिए सम्मान करना चाहिए क्योंकि मैं इस देश की राजनीति का सबसे कम उम्र का आडवाणी हूं। इसे कोई और कहे इससे पहले वह स्वयं कह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी पैसे लेकर भाग गया, लोग अजीब-अजीब बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। यह गलत बात है। प्रधानमंत्री जी साल डेढ़ साल में हमारे 15 लाख लौटाने के लिए पैसा जमा करते हैं तो कोई न कोई पैसे लेकर भाग जाता है। पिछली बार माल्या लेकर भाग गया तो इस बार नीरव मोदी लेकर। कुमार विश्वास यहीं नहीं रुके।उन्होंने कहा कि पिछली बार मैं चुनाव लड़ने आया तो कांग्रेस के संजय सिंह को राज्यसभा मिल गई। मेरे नाम के कारण दूसरे नामधारी को भी मिल गई।

उन्होंने कहा कि मैं इसी काम आता हूं कि जितने संजय नाम के हैं उन्हें राज्यसभा भिजवा सकूं। भाजपा पर तंज कसते हुए कुमार ने कहा कि बीजेपी वाले सोचते हैं कि नारियल टूटने वाला है। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि हम वो नारियल हैं जो टूटने पर उनके सिर पर ही गिरेंगे। अमेठी के विकास पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि अमेठी ने अपनी विरासत वैसी की वैसी ही बनाकर रखी है। जो गड्ढा जहां पर था वहीं पर है। उनकी हर बात पर लोगों ने खूब ठहाके लगाए।

»» डीरेका हत्याकांडः गैंगेस्टर की होगी कार्रवाई

DLW गेट से डबलू राय गिरफ्तार,

वाराणसी। डीरेका कर्मचारी नेता टीके मुकेश की हत्या के मुख्य आरोपी पंकज सिंह उर्फ डबलू राय को मंडुआडीह पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को दोपहर में एफसीआई गोदाम के पास डीएल डब्ल्यू गेट से गिरफ्तार किया। एसएसपी आरके भारद्वाज ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गलत जानकारी देकर पासपोर्ट बनवाने के कारण डबलू का पासपोर्ट रद्द किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि डबलू पर अब तक 16 मामले दर्ज हैं और मंडुआडीह थाने में हिस्ट्रीशीटर भी है। उसके खिलाफ 25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। डीरेका में डबलू राय और बबलू राय का इस कदर खौफ था कि बिना इसकी सहमति से कोई भी ठेकेदार कार्य नहीं कर सकता था।

सौ फीसदी ठेकेदारी में डबलू राय का हस्तक्षेप है। इसको देखते हुए इसके खिलाफ गैंगेस्टर की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गलत तरीके से कमाई गई सम्पत्ति को भी जब्त करने के लिए पत्राचार किया जाएगा। अब तक इस मामले में डीरेका के निलम्बित कर्मचारी रवि नारायण सिंह उर्फ बबलू राय और आशुतोष सिंह ने कोर्ट में समर्पण कर दिया था। वहीं अमित सिंह उर्फ रिक्कू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपी जेल में बंद हैं। उल्लेखनीय है कि गत 23 जनवरी को डीरेका में कर्मचारी नेता टीके मुकेश की हत्या उनके आवास के सामने ही कर दी गई थी।

झारखंड के पते पर बनवाया था पासपोर्ट

एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में डबलू ने बताया कि उसने झारखंड के पते पर पासपोर्ट बनवाया था। वहां पर उसने कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं होने की गलत जानकारी दी थी। अब डबलू के पासपोर्ट को निरस्त करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को लिखा गया है। मालूम हो कि पासपोर्ट बनवाकर डबलू कई देशों में घूमने गया था।

रवि के खिलाफ शीघ्र होगी बड़ी कार्रवाई

एसएसपी ने बताया कि बबलू राय ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाई थी। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके रेलवे के प्रमुख कार्मिक अधिकारी को भेज दी गई थी। जिसके आधार पर उसको निलम्बित कर दिया गया है। शीघ्र ही फर्जीवाड़ा करने में उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी होगी।

>> नजीब मामले से जुड़े 9 छात्र हो रहे प्रताड़ित : एबीवीपी

जेएनयू में आपत्तिजनक पोस्टर लगे, पुलिस में शिकायत

नई दिल्ली (एजेंसी)। जवाहरलाल नेहरू विविद्यालय में नजीब अहमद मामले से जुड़े नौ छात्रों को लेकर बीती रात कैम्पस में आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। इसकी जानकारी मिलने पर छात्रों ने इसकी शिकायत पुलिस में की और जिन्हें हटाया गया। जेएनयू एबीवीपी इकाई के अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि आखिर कब तक वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े लोग जेएनयू के दलित छात्रों को प्रताड़ित करेंगे। पिछले 16 महीने से निदरेष छात्रों को खासकर दलित एवं वंचित समाज से आने वाले छात्रों को कभी गुंडा, कभी मवाली, कभी हत्यारा कह के प्रताड़ित किया जा रहा हैं। कभी छात्रावास के मेस में, कभी शाम को ढाबा पर, कभी स्कूल क्षेत्रों, हर जगह इन छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या कसूर है इन छात्रों का बस यही की ए दलित है, कमजोर है। एक-दो को छोड़ दो तो ए किसी संगठन से भी नहीं है और वैचारिक लड़ाई भी नहीं हैं। कुछ लोग विशेष को खुश करने के लिए एवं अपनी चुनावी रोटी सेकने के लिए कब तक निदरेषों को सताते रहेंगे। कुमार ने बताया कि बीती रात बेशर्मी की सभी सीमा तोड़ कर वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े कुछ लोगो ने कैम्पस में पोस्टर्स लगाया, जिसमे जेएनयू के 9 छात्रों को दोषी दिखाया। इतना ही नहीं जब इन छात्रो ने विरोध प्रकट किया तो इनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों भी बोले गए। इन सभी पोस्टर्स में किसी संगठन का नाम नहीं था। क्या बिना किसी संगठन के नाम या व्यक्ति समूह के नाम का कोई पोस्टर लगाना जायज है। बात यही खत्म नहीं हुई इन लोगो ने गंदी गंदी गालिया दी और पशु की तरह काट देने की भी धमकी दी।

151 बार मुगदर भांजने पर मिलेगा 1.51 लाख का इनाम, जानें कहां

इलाहाबाद। रंगभरी एकादशी की पूर्व संध्या पर निकलने वाली मुगदर बारात में इस बार 151 बार मुगदर भांजने वाले पहलवान को 1.50 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। यह साहसिक प्रदर्शन 'धकाधक' की ओर से 25 फरवरी को निराला चौराहे पर होगा, जिसमें प्रदेश के कई जिलों के नामी पहलवान दमखम दिखाएंगे। प्रयाग की होली का अपना रंग और खास मिजाज है। रंगपर्व के उत्सव को और समृद्ध बनाती हैं इससे जुड़ी सांस्कृतिक परंपराएं, जिसे सैकड़ों वर्षों से लोग शद्दित से निभाते आ रहे हैं। इन परंपराओं में सबसे खास है मुगदर बारात। इसमें 6-7 पहलवान मुगदर भां कर अपने बल का प्रदर्शन करते हैं।

शिवमंगल दास का मुगदर है 140 पुराना

त्रिवेणी संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शंभुनाथ त्रिपाठी अंशुल ने बताया कि बारात में आकर्षण का केंद्र है, मुगदर की प्राचीनता और उसे भांजने की कला। इसमें प्रज्ञाचक्षु शिवमंगलदास महराज के यहां का 140 पुराना मुगदर है, जिसे उनके पिता राजाराम मश्रि ने 60 साल तक भांजा था। दूसरा मुगदर मद्रासी मुगदर कृष्णाराव का, तीसरा मुगदर ललई पहलवान का, चौथा बचन्नू गुरू, पांचवां सुरेन्द्र लाल, छठा धर्मराज पांडेय के यहां का शामिल किया जाता है।

»» यूपी बोर्ड की कॉपियां, 59 अरेस्ट

अलीगढ़ः एग्जाम सेंटर के बाहर लिखी जा रही थीं कॉपिया

अलीगढ़। अलीगढ़ के अतरौली के बोहरे किशनलाल इंटर कॉलेज तेबथू में नकल की शिकायत पर सीओ और एसडीएम की छापेमारी में बड़ा रैकेट पकड़ने का मामला सामने आया है। केन्द्र के पास के एक घर में कोडिंग वाली कॉपी लिखते 59 सॉल्वरों को घर को घेरकर नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया गया।

विद्यालय के संचालक व सभी सॉल्वरों के खिलाफ एफआईआर करा दी गई। वहीं परीक्षा निरस्त करते हुए केन्द्र को आजीवन डिबार करने की संस्तुति कर दी गई। वहीं संयुक्त निदेशक ने छबीलपर में लाला राम श्रीदेवी इंटर कॉलेज से संकलन केन्द्र पहुंचे बंडल में खेल होने पर परीक्षा निरस्त करने के बाद केन्द्र को डिबार करने की संस्तुति कर दी। गुरुवार को पुलिस ने 62 सोलवारों को पकड़ा था। इनमें से तीन महिलाओं को थाने से जमानत दे दी , जबकि 59 सोलवारों कोर्ट में पेश जेल भेज दिया। वहीं एसपी देहात ने बेटे की कॉपी लिखते कैमरे में कैद वर्दीधारी दारोगा की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

एसपी देहात डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि बौहरे किशन लाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक राजकुमार शर्मा व रामकुमार शर्मा की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी पाली में इंटर की रसायन विज्ञान की परीक्षा में अतरौली के तेबथू के बोहरे किशनलाल इंटर कॉलेज में नकल की शिकायत एडीएम प्रशासन आरएन शर्मा के पास आई। उनके निर्देश पर एसडीएम शिव कुमार और सीओ सुरेश कुमार मलिक प्राइवेट गाड़ी लेकर गांव पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने एक घर में चल रहे खेल का पूरा विश्वास होने पर गुपचुप तरीके से तैनात पुलिसकर्मियों को मकान को घेर लेने के आदेश दिए।

नाटकीय ढंग से आई पुलिस की घेराबंदी देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस ने घर के अंदर से करीब सौ लिखी हुई उत्तर पुस्तिकाओं को बरामद कर 58 सॉल्वरों को कॉपियां लिखते पकड़ा। मौके पर एडीएम प्रशासन आरएन शर्मा, एसपी देहात डॉ. यशवीर सिंह व एसडीएम शिव कुमार पहुंच गए। सभी पकड़े गए लोगों को मिनी बस में बैठाकर कोतवाली तक लेकर आए। रैकेट में शिक्षा विभाग में तैनात एक बाबू के कथित भाई के अलावा एक जन प्रतिनिधि के कथित चचेरे भाई व भतीजे समेत 58 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

विद्यालय के संचालक सहित सभी पकड़े गए लोगों के खिलाफ एफआईआर करा दी गई। वहीं डीआईओएस धर्मेन्द्र शर्मा ने एडीएम प्रशासन के निर्देश पर केन्द्र पर गुरुवार की परीक्षा निरस्त कर दी व परीक्षा केन्द्र को आजीवन डिबार करने की संस्तुति कर दी। वहीं दूसरी ओर संयुक्त शिक्षा निदेशक जितेन्द्र मलिक और नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज के प्राचार्य शीलेन्द्र कुमार के सचल दल ने अतरौली के छबीलपर में लाला राम श्रीदेवी इंटर कॉलेज में कॉपियों का बंडल बंधवाकर संकलन केन्द्र भेजवाया। लेकिन रास्ते में ही खेल कर दिया गया। जब उन्होंने संकलन केन्द्र पर बंडल देखा तो वह बदला हुआ सा मिला। वहां बंडल लेकर आने वाले लोग भी दूसरे थे। बंडल के साथ आए अभिलेख में काट पीट भी की गई थी। जेडी ने दोनों लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ एफआईआर करा दी, वहीं केन्द्र पर परीक्षा निरस्त करने के साथ ही डिबार करने की संस्तुति कर दी।

मेजर ध्यानचंद को भारत रतन नहीं दिए जाने पर उनके बेटे ने फिर दिया बड़ा बयान

अलीगढ़। जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय दुनिया में भारत की पहचान हॉकी और मेजर ध्यानचंद की वजह से होती थी। वह हमेशा से ही देश की प्रेरणा रहे हैं, लेकिन देश की आजादी के बाद से आज तक हॉकी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हमेशा ही उपेक्षित रहे। देश की सरकारों का ध्यान नहीं गया। उनको भारत रत्न न देना एक राजनीतिक साजिश है। यह बातें गुरुवार को अलीगढ़ आए मेजर ध्यानचंद के पुत्र और अर्जुन अवार्डी ओलंपियन अशोक ध्यानचंद ने कही। उन्होंने सभी सरकारों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें तो बहुत पहले भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए था।

डीएस कॉलेज में बेटी बचाओ, बेटी खिलाओ, राष्ट्र गौरव बढ़ाओ के तहत महिलाओं की हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन के लिए समिति के अन्य सदस्यों के साथ तैयारियों का जायजा लेने अलीगढ़ आए अशोक ध्यानचंद ने बताया कि मेजर ध्यानचंद को दुनिया में लगभग 55 देशों में 400 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जितना अपने खेल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध रहे हैं। उतना ही वे हिटलर की पेशकश ठुकराने की वजह से भी रहे हैं। बात 1936 की है, बर्लिन ओलंपिक खेलों के दौरान जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर जर्मनी की सेना में सबसे ऊंचे पद का प्रस्ताव दिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने उसे अपने देश भारत के लिए ठुकरा दिया। हालांकि उन्हें 1956 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया और उनके जन्मदिन को देश में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद भी उन्हें भारत रत्न देने के लिए अब तक की सरकारों ने कोई खास प्रयास नहीं किया। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलना भी एक तरह का विवाद है। हालांकि सचिन तेंदुलकर को इसमें दोषी नहीं माना जा सकता। क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के जरिए देश का काफी नाम किया है, लेकिन सरकार को उनको भारत रत्न देने की घोषणा करने से पहले ध्यानचंद और उनके हॉकी के योगदान पर जरूर सोचना चाहिए था। आगे कहा कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न न दिया जाना एक राजनीतिक साजिश है।

वह विजय अच्छी विजय नहीं है, जिसमें फिर से पराजय हो। वही विजय अच्छी है, जिस विजय की फिर विजय न हो -जातक

''मार्शल रेस'

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत यात्रा गंभीर विवाद में है। इस यात्रा को लेकर भारत में जो गहमागहमी दिखनी चाहिए, वह शुरू से नहीं दिखी। जिस तामझाम के साथ इस आतिय सत्कारी देश में उनका एहतराम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के प्रति जस्टिन की नरमीयत को लेकर खफा थे। फिर जिस तरह से उन्होंने भारत यात्रा के कार्यक्रमों में द्विपक्षीय मसलों से ज्यादा पर्यटन को तरजीह दिया, उसने भी गर्मजोशी नहीं बनने दी। कनाडा को आगे बढ़कर इसे संभालना चाहिए था, इसलिए कि विदेश मंत्रालय इसके लिए उसे बार-बार आगाह कर रहा था। यह करने के बदले जस्टिन ने भारतीय संप्रभुता का असम्मान कर तो हद ही पार कर दी। मुंबई में उनके सम्मान में दी गई डिनर पार्टी में जसपाल अटवाल जैसे खालिस्तान समर्थक का दिखना यह साबित करता है कि कनाडा की वह सोच बदली नहीं है। खालिस्तानी आंदोलन का वह अब भी हिमायती है, उस खूंखार आंदोलन का जिसने पंजाब में सैकड़ों जानें लीं, हजारों परिवारों को बेघर किया, जिसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को नहीं बख्शा और जो उन्मादी और जुनूनी भीड़ की तात्कालिक नफरत से उपजे देशव्यापी सिख विरोधी दंगों का कारक तत्व रहा। ट्रूडो कह भले रहे हों और उनका यह बयान भी आया है कि कनाडा की सरजमीन का इस्तेमाल खालिस्तानी ताकतों के लिए वह हरगिज नहीं होने देंगे, लेकिन उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं कि अटवाल उस पार्टी में आया कैसे? क्या उन्हें (ट्रूडे) एक राष्ट्र प्रमुख होने के नाते यह तक नहीं पता कि भारत ने बड़ी कुर्बानियों के बाद खालिस्तानी मंसूबों को हलाक किया है? ट्रूडो अपने इस दौरे के क्रम में अमृसर स्थित पवित्र स्वर्ण मंदिर भी गये, वहां मत्था टेका, कारसेवा की, रोटियां पकाई। निहितार्थ क्या था? निहितार्थ अगर यह संदेश देना था कि पंजाब की उस ''मार्शल रेस' को हम सलाम करने आए हैं, जिसमें अपने श्रम के बूते मिट्टी को सोना बनाने का साहस है तो उसका स्वागत है। लेकिन घोषित आतंकी को डिनर पार्टी में ले जाना सारा गुड़ गोबर कर देता है। उनकी सदिच्छा यहीं पर शक का बायस बनती है। यह सच है कि खालिस्तान आंदोलन को शह देने वालों में कनाडा एक प्रमुख देश रहा है। यह गलती तभी सुधर सकती है, जब वह पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर की सौंपी सूचियों पर कार्रवाई करते हुए उन नौ उग्रवादियों को भारत को सौंप दे।

देश की जनता

प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफनेपाल (यूएमएल) के नेता के. पी. शर्मा ओली और मार्क्सवादी सेंटर के नेता पुष्प दहल कमल प्रचंड ने अपनी पार्टियों के विलय का ऐतिहासिक फैसला किया है। उनके इस फैसले से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि यह उनका चुनावी वादा था। दोनों नेताओं के बीच विलय से संबंधित जो सहमति बनी है, उसके मुताबिक, पहले तीन साल ओली प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद के दो साल के कार्यकाल में प्रचंड प्रधानमंत्री होने का दायित्व संभालेंगे। इसी तरह यह भी समझौता हुआ है कि दोनों नेता संयुक्त रूप से चेयरमैन के रूप में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। नेपाल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा विलक्षण राजनीतिक प्रयोग होने जा रहा है। इसीलिए लोगों के मन में विलय के सवाल पर कई तरह की शंकाएं और दुविधाएं हैं। हालांकि पिछले दो-तीन दशकों से नेपाल जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता का दंश झेल रहा है, उसे देखते हुए दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के एकीकरण की घोषणा देश की जनता के पक्ष में है। यह एकीकरण नेपाल को सुशासन की ओर ले जाने में काफी मददगार हो सकता है। हाल में संपन्न हुए प्रांतीय और संसदीय चुनावों में वाम मोर्चे को भारी जनादेश मिला है। संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की कुल 275 सीटों में से सीपीएन-यूएमएल को 121 और माओवादी सेंटर को 53 सीटें मिली हैं, जो दो तिहाई बहुमत से थोड़ी बहुत ही कम हैं। यह जनादेश भी दोनों नेताओं को आपस में मिल कर सरकार चलाने का दबाव बना रहा है। दोनों पार्टियों के विलय के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नाम से अस्तित्व में आने वाली नईपार्टी का संयुक्त रूप से नेतृत्व करने वाले ओली और प्रचंड के बीच अगर कोई मतभेद पैदा होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। इसी तरह प्रचंड को नेतृत्व सौंपना ओली के लिए बहुत आसान नहीं होगा। फिर भी दोनों नेताओं से यह उम्मीद की जानी चाहिए कि नेपाल की जनाकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने के लिए वे अपने-अपने अहं को छोड़कर विलय की प्रक्रिया को उसके वांछित मुकाम तक पहुंचाएंगे और नेपाल को लोकतांत्रिक पथ पर अग्रसर कराएंगे।

जनप्रतिनिधियों की ''भागीदारी'

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद से सियासी लड़ाई सार्वजनिक और बेपर्दा हो गई। इसके पीछे की वजह को जाने बिना इस संकट को हल नहीं किया जा सकता। भारत में 29 राज्य हैं और सात केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनका शासन चलाने की जिम्मेदारी संविधान ने भारत सरकार को दी है। जो 29 राज्य हैं, वे स्वतंत्र हैं और वहां चुनाव होते हैं। जो चुनकर आते हैं, वह हुक्मरान बन जाते हैं और वहां की सरकार चलाते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके शासन संचालन की व्यवस्था भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। चूंकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर चलते हैं, लिहाजा स्पष्ट है कि सरकार केंद्र चलाएगा।

सतीश पेडणोकर

आप सरकार के साथ यह परेशानी थी कि इन्हें पूर्व की राजनीति या शासन करने का कोई अनुभव नहीं था। इन्हें मुगालता है कि जनता जिसे चुनती है, वही बादशाह होता है। इन्होंने सत्ता में आते ही वो तुगलकी फरमान देने शुरू किए, जिसकी संविधान में स्पष्ट तौर पर मनाही है। उदाहरण के लिए, जो पहला आदेश इन्होंने जारी किया- जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था से जुड़ी हुई फाइलें जो सीधे उप राज्यपाल के पास जाती है, वे मुख्यमंत्री के पास से होकर जाएं

दिल्ली की सरकार एक बार फिर विवादों में है। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के आठ-दस विधायकों की हाथापाई, वाद-विवाद और मारपीट की वारदात से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सियासी और प्रशासनिक संकट चरम पर पहुंच गया है। फिलहाल कामकाज ठप है, विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक पैंतरेबाजी और जोर-आजमाइश का खेल बदस्तूर है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद से सियासी लड़ाई सार्वजनिक और बेपर्दा हो गई। इसके पीछे की वजह को जाने बिना इस संकट को हल नहीं किया जा सकता। भारत में 29 राज्य हैं और सात केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनका शासन चलाने की जिम्मेदारी संविधान ने भारत सरकार को दी है। जो 29 राज्य हैं, वे स्वतंत्र हैं और वहां चुनाव होते हैं। जो चुनकर आते हैं, वह हुक्मरान बन जाते हैं और वहां की सरकार चलाते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके शासन संचालन की व्यवस्था भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। चूंकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर चलते हैं, लिहाजा स्पष्ट है कि सरकार केंद्र चलाएगा। इन सात केंद्र शासित राज्यों में पांच प्रदेश-दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़-अलग वर्ग के हैं। यहां कोई चुनी हुई व्यवस्था नहीं है। यहां जो प्रशासक है, उसे अपने हिसाब से राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और वह इनकी सलाह से सरकार चलाता है। इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर (उप राज्यपाल) भी कहा जाता है। साठ के दशक में इस मांग ने जोर पकड़ा कि जो सात केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके यहां के जनप्रतिनिधियों की ''भागीदारी' भी शासन चलाने में होनी चाहिए। तो प्रयोग या कहें तर्जुबे के तौर पर यह किया गया कि पुडुचेरी में कुछ लोग चुने जाएं और प्रशासक यानी उप राज्यपाल को कहा जाए कि वह इनसे सलाह-मश्विरा कर के सरकार चलाएं। अगर आप जनता को शामिल करना चाहते हैं सरकार चलाने के लिए तो आपको एक संस्था बनानी होगी, सो एक संस्था बनाई गई, जिसे विधान सभा कहा गया। फिर वहां चुनाव हुआ और जो 30 सदस्य चुने गए उप राज्यपाल को कहा गया कि इन मेंबर्स से सलाह करके सरकार चलाएं। दूसरे शब्दों में, विधान सभा और विधान सभा से निकली हुई 5-6 मंत्रियों की एक कमेटी बनी जिसे कैबिनेट कहा गया और एक को उसका मुखिया यानी मुख्यमंत्री। उनसे कहा गया कि आप ''एड' और ''एडवाइस' किया कीजिए, प्रशासक को पांडिचेरी का शासन चलाने में। यह व्यवस्था पिछले 50-60 साल से पांडिचेरी में चल रही है। इसी के तर्ज पर 1993 में दिल्ली में एक नया सिस्टम बनाया गया क्योंकि यहां जोर मारा जा रहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाओ। इस मांग के लिएसारे दल, भाजपा, कांग्रेस व अन्य दल एकजुट थे। क्योंकि पूर्ण राज्य का अर्थ होता है, ''सत्ता और शक्तियां' चुने हुए लोगों के हाथों में आ जाएगी। तो जितने विधायक और अन्य सियासी लोग थे, उन्हें यह सूट करता था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दरजा मिलते ही इन लोगों की हनक यहां बन जाएगी। जो मलाईदार सारे महकमे, पुलिस आदि इनके अंदर आ जाए। तो इनका सिर्फएक ही संकुचित उद्देश्य था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दरजा मिले और हम मजबूत हो जाएंगे।

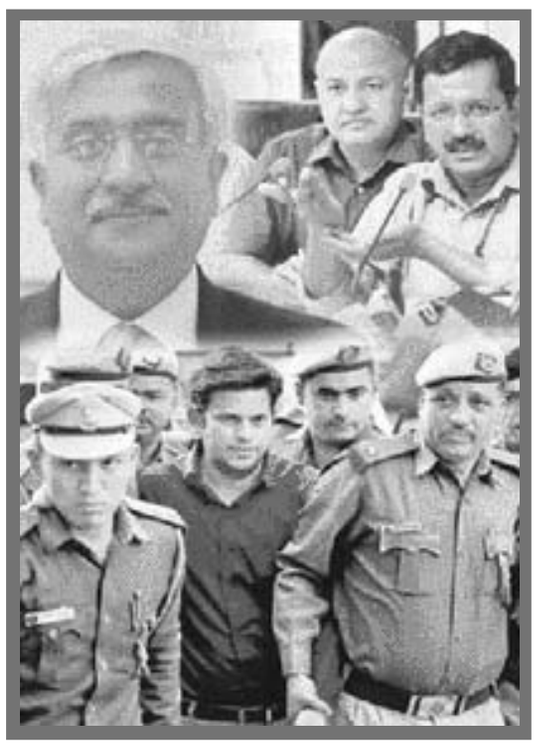

हालांकि जनता को इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं था। यही वजह है कि पूर्ण राज्य का मसला यहां कभी ''जन आंदोलन' नहीं बन सका। इन सब बातों को देखते हुए एक कमिटी 1987 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर.एस. सरकारिया के नेतृत्व में गठित हुई, जिसे सरकारिया बालाकृष्णन कमेटी कहते हैं। कमिटी ने देश भर में दो साल घूमकर कई गणमान्य लोगों से बात करके अपनी रिपोर्ट तैयार की। चूंकि दिल्ली को राज्य बना नहीं सकते और न ये हित में होगा, तो यह उपाय निकाला गया कि इसे कुछ शक्तियां दी जाएंगी। और ये शक्तियां संविधान बनाके देने की बात कही गई, अलग से कानून बनाकर शक्ति देने की बात नहीं कही गई; क्योंकि संविधान में परिवर्तन करना आसान नहीं होगा। इसके लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए। इसलिए विचार हुआ कि दिल्ली को फुटबॉल नहीं बनने देंगे क्योंकि कोई भी दल दिल्ली में सत्ता में आएगी तो वह अपने हिसाब से बदलाव कर हालात को पेचीदा बना देगी। सो, दिल्ली के लिए एक व्यवस्था बनाई गई और उसमें चार-पांच चीजें डाली गई। कहा गया कि रहेगी तो ये केंद्र शासित प्रदेश ही, मगर हम इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रख देते हैं। दूसरा, यहां एक प्रशासक होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति सीधे शासन नहीं करेंगे, प्रशासक के माध्यम से करेंगे। उस प्रशासक का नाम होगा उप राज्यपाल। यहां चुनाव भी होगा और महानगर परिषद की जगह विधान सभा होगा। मुख्य कार्यकारी पार्षद की जगह मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली प्रशसन की जगह दिल्ली सरकार रख दिया गया। फिर विधान सभा को स्पष्ट किया गया कि आपकी शक्तियां सीमित होंगी। आप कुछ विषयों पर ही कानून बना सकते हैं। दिल्ली सरकार को भी बता दिया गया कि कुछ विषय जिस पर आप कानून नहीं बना सकेंगे, वह है; पुलिस, जमीन और कानून-व्यवस्था। तो कमिटी ने कहा कि ये तीन शक्तियां हम आपको नहीं देंगे। दिक्कत की बात यह है कि दिल्ली में वर्तमान में जो केजरीवाल की सरकार है, वह अपने आपको भले चुनी हुई जनता की सरकार कहें। परंतु उन्हें नियम-कायदा बिल्कुल नहीं मालूम कि दिल्ली में सालों पुरानी व्यवस्था है कि यहां का मुख्यमंत्री शासन में सिर्फ ''भागीदार' है और असली शासक उप राज्यपाल है। और उससे सलाह करके ही सरकार चलाई जा सकती है। कोई भी काम बिना उप राज्यपाल को बताए या उनसे पूछे नहीं किया जा सकता है। 1993 से 2014 तक शासन करने वाले मुख्यमंत्रियों-मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित-ने यही किया। आप सरकार के साथ यह परेशानी थी कि इन्हें पूर्व की राजनीति या शासन करने का कोई अनुभव नहीं था। इन्हें यह भी मुगालता था और है कि जनता जिसको चुनती है, वही असली बादशाह होता है। इन्होंने सत्ता में आते ही वो तुगलकी फरमान देने शुरू किए, जिसकी संविधान में स्पष्ट तौर पर मनाही है। उदाहरण के लिए, जो पहला आदेश इन्होंने जारी किया-जमीन, पुलिस और कानून-व्यवस्था से जुड़ी हुई फाइलें जो सीधे उप राज्यपाल के पास जाती है, मुख्यमंत्री के पास से होकर जाए। यह विषय ही नहीं है इनका। और इस तरह टकराव बढ़ता ही गया, और हालात अब विषम हो चले हैं।

चलते चलते

''नरम द्रविड़ अस्मिता'

जयललिता के निधन के बाद से तमिलनाडु में दो अभिनेताओं पर लोगों की निगाहें बराबर जमी हुई थीं। रजनीकांत और कमल हासन। रजनीकांत की राजनीति में आने की सुगबुगाहट तो लम्बे समय से है, लेकिन हमेशा वे इसे टालते रहे हैं। हाल में उन्होंने अगला विधान सभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, पार्टी की घोषणा बाकी है। हासन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पार्टी और उसके सिद्धांतों की घोषणा करते राज्यव्यापी दौरा भी शुरू कर दिया। दरअसल, तमिलनाडु की राजनीति पर सिनेमा का जबरदस्त प्रभाव रहा है। इसका अंदाजा इस तय से लगाया जा सकता है कि 1967 में सीएन अन्ना दुरई द्वारा राज्य की कमान संभालने के बाद क्रमश: एम. करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन और जयललिता के हाथों में ही राज्य की कमान

सरकार ने कहा जी हम तो ही इतना देते हैं बस। रेट यही है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि पीड़िता तक पंहुचते-पंहुचते यह रकम घटेगी नहीं। अब अदालत की नाराजगी तो जी सिर मत्थे। लगता है अदालत को सिर-मत्थे जनता ही रखती है। सरकार तो रखती नहीं। रखती तो आधार पर ऐसी किच-किच थोड़े ही मचती। बल्कि जनता ने तो अदालत की पीड़ा

रही है। अन्ना दुरई और करुणानिधि जहां पटकथा लेखक रहे, वहीं रामचंद्रन और जयललिता अपने अभिनय के दम पर लोगों के जेहन में छा गए गए। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में रजनीकांत और कमल हासन द्वारा राजनीति में आने की घोषणा के बाद तमिलनाडु में मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है। अभी तक तमिलनाडु की राजनीति दो ध्रुवीय थी, जिसमें एक तरफ डीएमके तो दूसरी तरफ एआईडीएमके। बारी-बारी से सत्ता इन्हीं दोनों दलों के बीच ही रही। ऐसे में कयास लगाये जा रहे हैं कि सत्ताधारी एआईडीएमके का बिना किसी चमत्कारी नेतृत्व के अपना अस्तित्व बचा पाना कठिन होगा। उसके पास जयललिता जैसा सम्मोहक नेता नहीं है। वहीं, करुणानिधि की पार्टी डीएमके की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। कारण करुणानिधि की उम्र और उनके परिवार में व्याप्त गुटबंदी है। राज्य की राजनीति में राष्ट्रीय दलों की नाममात्र की उपस्थिति है। कांग्रेस और भाजपा किसी न किसी के साथ गठबंधन करके ही चुनाव में उतरती हैं। कमल हासन ने ''नरम द्रविड़ अस्मिता' की ओर रुझान तय कर अपनी राजनीतिक धारा स्पष्ट कर दी है, वहीं अब 2004 के लोक सभा चुनाव में भाजपा के लिए अपील करने वाले रजनीकांत पर सभी की निगाहें हैं। वैसे तमिलनाडु के मतदाता सिर्फ आकर्षित नहीं होते बल्कि सम्मोहित हो जाते हैं।

फोटोग्राफी...

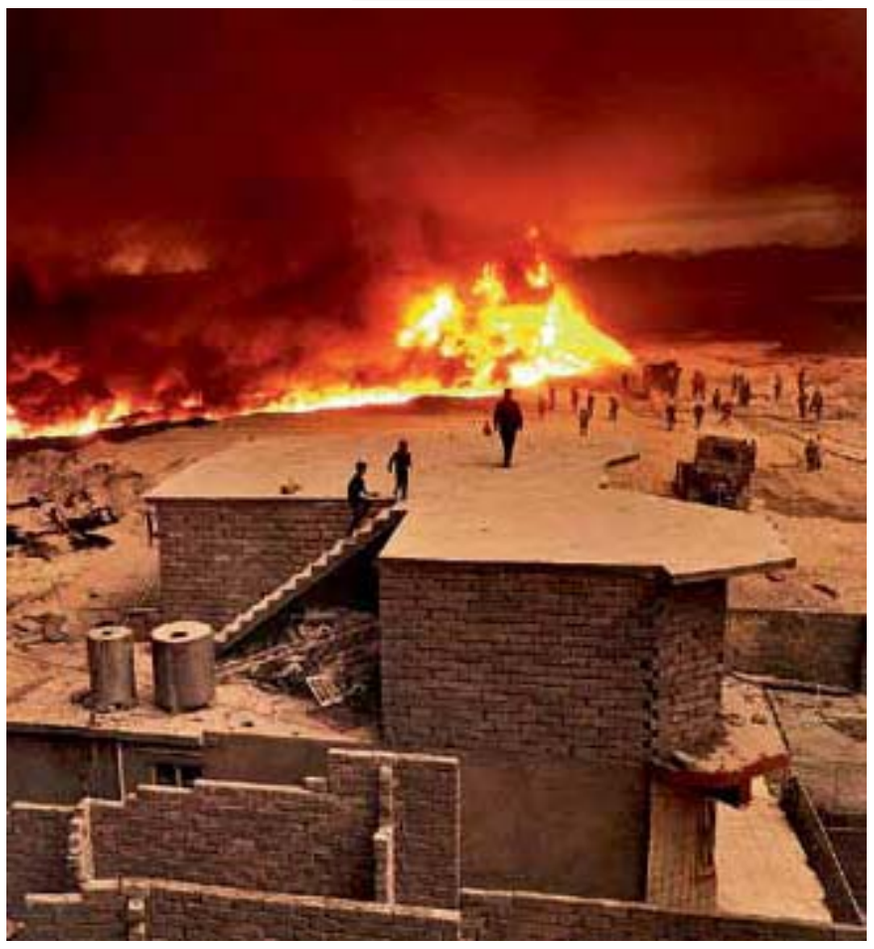

यह फोटो इराक के उस वॉर ज़ोन का है जब वहां की सेना आईएस के आतंकि यों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रही थी। मोसुल व आसपास के शहरों में आईएस ने कब्जा कर लिया था, तब जॉय लॉरेन्स (28) वहां अपना ड्रोन कैमरा लेकर पहुंचे थे। कनाडाई मूल के जॉय ने न्यू यॉर्क में कामसी खा, अब वे वॉर ज़ोन फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। कय्या राह शहर के तेल कुएं में आग का यह फोटो जॉय के उस कलेक्शन का हिस्सा है, जो उन्होंने ब्रिटि श एनजीओ ऑक्सफेम के लिए तैयार किया था। उनके कारण इराकी व उसकी सहयोगी सेना को आईएस आतंकि यों की अलग- अलग लोकेशन पता करने में मदद मिली थी। वे कहते हैं, वॉर ज़ोन में हेलिकॉप्टर से फोटोशूट करना जोखिमभ रा होता है। पता नहीं कब कहां से उस पर हमला हो जाए इसलिए ड्रोन फोटोग्राफी ज्यादा मदद गार होती है। ऑक्सफेम इराक में व्यापक स्तर पर उन लोगों की मदद कर रहा है, जिन्हें युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ और घरों ड्डके श्वक्षतिग्र स्त होने से पलायन करना पड़ा। youtube.com

सत्संग

''सुपरमैन'

सही है कि जिम्मेदारी की कोई सीमा नहीं, लेकिन आपकी कार्यशक्ति सीमित होती है। भले ही आप ''सुपरमैन' हों, आपकी काम करने की क्षमता एक सीमा के अंदर होती है। जिम्मेदारी अलग चीज है और आप क्या कर सकते हैं अलग चीज है। जो लोग दोनों के बीच का अंतर नहीं समझ पाते, वे जिम्मेदारी का नाम लेते ही तनाव में आ जाते हैं। आप अपनी क्षमता के अंदर ही कार्य कर सकते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति के समान काम नहीं कर सकते। क्योंकि उनकी क्षमता अलग तरह की है। आपकी बुद्धि, क्षमता, परिवेश जैसे अनेक मानदंडों के आधार पर आपके कार्य का निर्णय किया जाता है। लेकिन जिम्मेदारी लेने का निर्णय आपकी इच्छा पर ही है। वहां और कोई अड़चन नहीं है। जिम्मेदारी को काम के रूप में समझने की वजह से वह भार जैसा लगता है। तो क्या आप सारे कामों को कर सकते हैं? कई मौकों पर आप कुछ भी किए बिना बैठे रहे, वह भी तो जिम्मेदारी ही है। लेकिन उत्तरदायित्व लेने की भावना से आपकी कार्यशक्ति सहज रूप से विकसित होती है। तब कोई हिचकिचाहट नहीं होती। सड़क पर खेल रहा आपका बच्चा अगर गिर पड़े, तो भागे-भागे जाकर उसे उठाकर अपने आगोश में ले लेंगे। उस समय आपके अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। लेकिन पड़ोसी के बच्चे के गिर जाने पर कुछ लोग मूर्खतापूर्ण ढंग से हिसाब-किताब लगाते हैं, ''क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं?' जिम्मेदारी का अनुभव करने पर उस परिस्थिति में जो काम किए जाने की जरूरत होगी, उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करके आप निश्चित रूप से कर देंगे। इस तरह परिस्थिति के अनुरूप काम का चयन करके निर्णय लेने की पूरी आजादी आपको है। जिम्मेदारी की सरहदों को हटा देंगे तो जो भी आपसे संभव होगा अवश्य कर देंगे। जो काम आप से संभव नहीं है उसे आप कर नहीं सकते। लेकिन आपसे जो काम हो सकता है उसे जरूर कर देंगे। जब कोई ऐसा सोचता है, ''मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं' तब वह उस काम को भी नहीं करेगा, जो उससे हो सकता है। इस तरह के जीवों के जिंदा रहने का प्रयोजन ही क्या है? अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करने से आपके कार्य करने का बटन आपके हाथ में आ जाता है। आपकी संपूर्ण क्षमता आपके अंदर से प्रकट होती है।

प्लास्टिक का नुकसान

प्लास्टिक के विकल्प ने यों तो हमारी जिंदगी को आसान किया है। पॉलीथिन की थैलियां और प्लास्टिक की चीजें (रंगबिरंगे पेन-पेंसिल से लेकर डिजाइनर लंच बॉक्स और पानी की बोतलें) हमारे जीवन में अनायास नहीं आई। उन्हें साइंस की तरक्की और उनसे मिलने वाली सुविधा ने जीवन में शामिल कराया है। अमेरिकी साइंटिस्टों का आकलन है कि पिछले 65 सालों में पूरी दुनिया में 8.3 अरब टन प्लास्टिक का निर्माण हुआ है। निश्चय ही प्लास्टिक ने काफी सुविधाएं दीं, लेकिन समस्या यह है कि इसका 70 फीसद हिस्सा अब कबाड़ (प्रदूषित-जहरीले कचरे) के रूप में धरती पर मौजूद है। प्लास्टिक का सबसे खराब पहलू यह है कि इसका उपयोगी जीवन छोटा है और कूड़े के रूप में इसकी जिंदगी काफी लंबी है।

प्लास्टिक की कोई थैली हो सकता है कि एक दिन से लेकर साल भर तक इस्तेमाल में आए, लेकिन फेंकने पर उसे पर्यावरण में नष्ट होकर घुलने में कई सौ या हजार साल भी लग सकते हैं। ऐसे में यहां-वहां कबाड़ में फेंक दी गई पॉलिथिन की थैलियां और प्लास्टिक के लंच बॉक्स, बोतलों से लेकर तमाम सामान या तो भोजन समझ लिये जाने पर गायों आदि जानवरों के पेट पहुंचते हैं या कबाड़ के रूप में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। हाल में पटना में बिहार वेटनेरी कॉलेज में एक गाय के पेट से 80 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा निकाला गया। साल भर पहले अहमदाबाद के जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट में भी इसी तरह इलाज के लिए लाई गई एक बीमार गाय के पेट से 100 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा निकला था। कुछ साल पहले उत्तर भारत के एक चिड़ियाघर का दरियाई घोड़ा अचानक मर गया, उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो पता चला कि उसके पेट में दो किलो से ज्यादा पॉलीथिन थैलियां जमा थीं। एक अनुमान है कि हर साल 20 लाख से ज्यादा पशु, पक्षी और मछलियां पॉलिथिन थैलियों के चलते अपनी जान गंवाते हैं। आज हर कोई पॉलीथिन और प्लास्टिक की थैलियों की वजह से पर्यावरण और हमारे जीवन पर पड़ने वाले खराब असर की बात करता है, पर मजबूरी यह है कि पाबंदी के सिवा किसी को इसका ठोस विकल्प नहीं सूझ रहा है। अस्सी के दशक में जब पॉलीथिन की थैलियां कागज और जूट के थैलों का विकल्प बनना शुरू हुई थीं, तो लोग इन्हें देखकर हैरान थे। वर्ष 2013-14 के दौरान देश में 1.1 करोड़ टन प्लास्टिक की खपत हुई, जिसके आधार पर यह जानकारी प्रकाश में आई कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहर सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा निकाल रहे हैं। प्लास्टिक से होने वाले खतरों से जुड़ी एक चेतावनी अगस्त, 2015 में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने जारी की थी। उन्होंने प्लास्टिक से बने लंच बॉक्स, पानी की बोतल और भोजन को गर्म व ताजा रखने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली पतली प्लास्टिक फॉइल के बारे सचेत किया कि इनमें 175 से ज्यादा दूषित घटक होते हैं, जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं खतरों के मद्देनजर 2016 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके दवाओं को प्लास्टिक से बनी शीशियों व बोतलों में पैक करने पर रोक लगाने का इरादा जाहिर किया था। पर सवाल यह है कि जिस पॉलीथिन और प्लास्टिक ने हमारी जिंदगी को आसान किया है, क्या बिना विकल्प सुझाए उसका इस्तेमाल रोक पाना संभव है? अब यह सवाल असल में साइंस और इंजीनियरिंग के लिए ज्यादा जरूरी है कि वहां इनका इससे बेहतर नहीं तो, समकक्ष समाधान अवश्य सुझाया जाए।

रूसी बाबस्लेडर नादेज्दा सर्गेयेवा डोपिंग में पकड़ा गया : महासंघ

मास्को। रूसी बाबस्लेडर नादेज्दा सर्गेयेवा को प्योंगचांग में चल रहे शीतकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया है। रूस के बाबस्लेग महासंघ ने जानकारी दी। महासंघ ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा, ''रूसी टीम के पायलट नादेज्दा सर्गेयेवा का 18 फरवरी को किया गया डोपिंग परीक्षण दिल की बीमारी के लिये ली जाने वाली दवा के सेवन के लिये पाजीटिव पाया गया है। यह दवा प्रतिबंधित सूची में शामिल है।' महासंघ के अनुसार इससे पहले 13 फरवरी को किया उनका परीक्षण नेगेटिव रहा था।

कोरिया दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान, रानी को सौंपी गई कमान

नयी दिल्ली। अनुभवी स्ट्राइकर रानी रामपाल कोरिया के खिलाफ सत्र की शुरूआती श्रृंखला के लिये 20 सदस्यीय भारतीय महिला हाकी टीम की कप्तान होंगी। भारतीय टीम तीन से 12 मार्च तक कोरिया के खिलाफ पांच मैच खेलेगी। फारवर्ड पूनम रानी फिट होकर टीम में लौटी है। डिफेंडर सुनीता लाकड़ा को उपकप्तान बनाया गया है। गोलकीपर सविता को इस दौरे के लिये आराम दिया गया है। गोलकीपिंग की जिम्मेदारी रजनी ई और नयी खिलाड़ी स्वाति पर होगी। डिफेंस में अनुभवी दीपिका , सुमन देवी , दीप ग्रेस इक्का, सुशीला चानू और गुरजीत कौर हैं। वहीं मिडफील्ड का जिम्मा मोनिका, नमिता टोप्पो, निक्की प्रधान, नेहा गोयल, उदिता और लिलिमा मिंज पर होगा। रानी, वंदना कटारिया, लालरेमसियामी, नवजोत कौर, नवनीत कौर और पूनम फारवर्ड पंक्ति संभालेंगे। पिछले साल नवंबर में चीन को हराकर एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम का यह पहला टूर्नामेंट है। मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा कि, 'सत्र के पहले टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन बहुत जरूरी है। इससे लय मिलती है। कोरिया दौरे से पता चलेगा कि राष्ट्रमंडल खेलों से पहले हमें कहां सुधार करने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि,'हमारे पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से सजी टीम है। ये लड़कियां जबर्दस्त फिट हैं और यो यो टेट में अच्छा स्कोर कर रही है। इनमें से अधिकांश ने रांची में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया था और उम्मीद है कि यह लय कायम रहेगी।'

स्विस ओपन : गुरूसाईदत्त, समीर स्विस ओपन के क्वार्टर फाइनल में

बासेल। राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता आरएमवी गुरूसाईदत्त और सैयद मोदी ग्रां प्री विजेता समीर वर्मा ने आज यहां पुरुष एकल में विपरीत हालात में जीत के साथ स्विस ओपन विश्व सुपर 300 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। टखने की चोट के बाद वापसी कर रहे गुरूसाईदत्त ने हमवतन सौरभ वर्मा को सीधे गेम में 21-18 21-14 से हराया जबकि दूसरे वरीय समीर को जापान के यू इगाराशी को 11-21 21-18 21-16 से हराने के लिए जमकर पसीना बहाना पड़ा। अगले दौर में गुरूसाईदत्त थाईलैंड के केंटाफोन वांगचारियोन जबकि समीर जापान के केंटो मोमोटा से भिड़ेंगे। महिला एकल में साई उत्तेजिता राव चुक्का को हालांकि जापान की दूसरी वरीय मिनात्सु मितानी के खिलाफ 8-21 13-21 से हार का सामना करना पड़ा। कल रात पुरुष युगल में अर्जुन एमआर और रामचंद्रन श्लोक की भारतीय जोड़ी ने पो ली वेई और यांग मिंग से की चीनी ताइपे की जोड़ी को 21-17 14-21 21-15 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। अनुरा प्रभुदेसाई हालांकि शीर्ष वरीय जापान की सयाका ताकाहाशी के खिलाफ 12-21 12-21 की शिकस्त से प्रतियोगिता से बाहर हो गई।

मणिपुर में विश्व स्तरीय फुटबाल अकादमी का होगा निर्माण!

नयी दिल्ली। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि उनका मंत्रालय राज्य सरकार के साथ मिलकर मणिपुर में विश्व स्तरीय फुटबाल अकादमी खोलने पर सक्रियता से विचार कर रहा है। राठौड़ ने मणिपुर के 11 से 16 बरस के छात्रों से बातचीत के दौरान यह बात कही। ये छात्र असम राइफल्स द्वारा आयोजित 'नेशनल इंटीग्रेशन टूर' पर यहां आए हैं।

मंत्री ने कहा कि फीफा अंडर 17 विश्व कप की भारतीय टीम में मणिपुर के आठ खिलाड़ी शामिल थे और उन्होंने छात्रों से अपनी पसंद के खेल में कड़ी मेहनत करने को कहा जिससे कि वे भविष्य में खेल इंडिया स्कूल खेलों में हिस्सा ले सकें।

खेल मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा, 'मणिपुर के चंदेल जिले के 20 छात्रों का समूह अपने शिक्षकों के साथ यहां खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मिला। राठौड़ ने छात्रों से उनके शौक, शिक्षा और खेलों में रुचि के बारे में पूछा।' उन्होंने कहा, 'उन्होंने (राठौड़) कहा कि मंत्रालय मणिपुर में राज्य सरकार के साथ मिलकर विश्व स्तरीय फुटबाल अकादमी स्थापित करने पर सक्रियता से विचार कर रहा है।'

तीसरा टी20 जीतकर दौरे का शानदार अंत करना चाहेगी टीम इंडिया

केपटाउन (एजेंसी)।

भारतीय टीम निर्णायक तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरेगी तो उसका इरादा उतार चढाव से भरे इस दौरे का जीत के साथ शानदार अंत करने का होगा। पिछले मैच में मिली हार के झटके से उबरते हुए विराट कोहली की टीम आठ सप्ताह लंबे इस दौरे को एक और श्रृंखला जीतकर अंजाम तक पहुंचाना चाहेगी। तीन मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 से बराबर है। भारत ने जोहानिसबर्ग में पहला टी20 मैच 28 रन से जीता। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने सेंचुरियन में छह विकेट से जीतकर बराबरी की। भारत ने न्यूलैंड्स पर कभी टी20 क्रिकेट नहीं खेला है। यहां भारत का यह पहला टी20 मैच है जबकि दक्षिण अफ्रीका ने यहां आठ टी20 खेलकर पांच गंवाये हैं। उसे दो जीत 2007 टी20 विश्व कप में मिली और द्विपक्षीय श्रृंखला में एकमात्र जीत 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ मिली थी। दक्षिण अफ्रीका ने दिखा दिया है कि टी20 प्रारूप उसे अधिक रास आता है। उसने वर्षाबाधित पिंक वनडे जीता और इस श्रृंखला के पहले मैच में भी 204 रन का लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंचा था। पिछले मैच में कार्यवाहक कप्तान जेपी डुमिनी ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए रणनीति पर अमल किया। अब देखना यह होगा कि मेजबान टीम अपनी गेंदबाजी की क्या रणनीति बनाती है और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिये क्या करती है। पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम एकादश में बदलाव नहीं किया और अब यह देखना होगा कि निर्णायक मैच में भी क्या वे इस पर कायम रहते हैं। जोन जोन स्मट्स प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे हैं जबकि डेविड मिलर भी खराब फार्म में है।

भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह पेट में खिंचाव के कारण बाहर रहे थे। अभी भी उनका खेलना तय नहीं है। टीम प्रबंधन उन्हें लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगा क्योंकि श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला दो सप्ताह बाद ही खेलनी है। भारतीय गेंदबाजों में जयदेव उनादकट काफी महंगे साबित हुए जिन्होंने 9-78 की औसत से 75 रन दिये। युजवेंद्र चहल ने आठ ओवर में 103 रन देकर एक विकेट लिया। ऐसे में कोहली गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव की सोच सकते हैं। बुमराह के खेलने पर उनादकट को बाहर रखा जा सकता है। शरदुल ठाकुर ने चार ओवर में 31 रन देकर एक विकेट लिया था। भारतीय टीम अक्षर पटेल को भी उतार सकती है जिससे तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में हार्दिक पंड्या पर फोकस होगा।

भारतीय महिला टीम की निगाहें दक्षिण अफ्रीका से सीरीज जीतने पर

केपटाउन (एजेंसी)।

श्रृंखला में 2-1 की बढत बना चुकी भारतीय महिला क्रिकेट टीम कल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 मैच में उतरेगी तो उसका इरादा वनडे के बाद इस प्रारूप में भी श्रृंखला अपने नाम करने का होगा। भारत ने तीन मैचों की वनडे श्रृंखला 2-1 से जीती और पांच मैचों की टी20 श्रृंखला में 2-1 से आगे है। बारिश के कारण सेंचुरियन में चौथा मैच नहीं हो सका और अब पांचवें मैच में जीत दर्ज करके हरमनप्रीत कौर की टीम दौरे का शानदार अंत करना चाहेगी।

पहले दो टी20 मैचों में भारत ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए सात और नौ विकेट से जीत दर्ज की लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने तीसरा मैच पांच विकेट से जीतकर श्रृंखला में उम्मीदें बरकरार रखी है। चौथे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15-3 ओवर में तीन विकेट पर 130 रन बना लिये थे लेकिन बारिश के कारण खेल रद्द हो गया। भारतीय टीम अगर कल जीतती है तो दक्षिण अफ्रीका के एक ही दौरे पर दो श्रृंखलायें जीतने वाली पहली भारतीय टीम हो जायेगी। इससे पहले भारत ने आस्ट्रेलिया में टी20 श्रृंखला जीती थी। सीनियर खिलाड़ी मिताली राज ने पहले दो मैच में 54 और 76 रन बनाये लेकिन तीसरे मैच में खाता भी नहीं खोल सकी। स्मृति मंधाना ने तीन मैचों में 28 , 57 और 37 की पारियां खेली। तीसरे टी20 में हरमनप्रीत ने 30 गेंद में 48 रन बनाये लेकिन मध्यक्रम के पतन के कारण भारतीय पारी 17-5 ओवर में 133 रन पर सिमट गई। वेदा कृष्णामूर्ति ने नाबाद 37 और 23 रन बनाये ।इस बार भी बल्लेबाजी का दारोमदार मिताली, स्मृति और हरमनप्रीत पर होगा।

गेंदबाजी में आफ स्पिनर अनुजा पाटिल ने पहले तीन मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट लिये लेकिन चौथे मैच में 44 रन दे डाले। स्पिनर पूनम यादव और तेज गेंदबाज पूजा वस्त्रकार ने भी अभी तक चार चार विकेट लिये हैं ।नयी गेंद संभालने वाली शिखा पांडे प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर सकी है। दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिये कप्तान डी वान नीकर्क तीसरे मैच के प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगी। तीसरे मैच में तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने पांच विकेट लिये।

बीसीसीआई मीडिया अधिकार : सदस्यों को अंधेरे में रखा गया, सीओए ने ई-नीलामी का किया फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)।

प्रशासकों की समिति (सीओए) ने अपनी नीलामी की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए फैसला किया कि आगामी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिये बीसीसीआई के मीडिया अधिकार (प्रसारण और डिजिटल) ई-नीलामी के जरिये किये जायेंगे। पहले इनका निर्धारण सीलबंद टेंडर प्रक्रिया के तहत किया जाता था जो इस साल आईपीएल में इस्तेमाल की गयी थी।

ई-नीलामी के 27 मार्च को होने की उम्मीद है। इन अधिकारों कों तीन वर्गों में बांटा गया है- जो वैश्विक टीवी अधिकार और शेष विश्व डिजिटल अधिकार पैकेज, भारतीय-उपमहाद्वीप डिजिटल अधिकार पैकेज और वैश्विक संयुक्त अधिकार पैकेज हैं। हालांकि विनोद राय की अध्यक्षता वाली सीओए ने ज्यादातर नीतिगत फैसले अकेले ही ले लिये हैं और इसके लिये बीसीसीआई की आम सभा बैठक को भी नहीं बुलाया।

एक नाराज सीनियर अधिकारी ने आज पीटीआई से कहा, 'हां, हमें एक नोट मिला है जिसमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिये बीसीसीआई के मीडिया अधिकार ई-नीलामी प्रक्रिया के जरिये किये जायेंगे। अब इस नोट में इसका जिक्र नहीं किया गया है कि अचानक से यह फैसला क्यों किया गया जबकि बीसीसीआई ने पूर्व प्रक्रिया से आईपीएल अधिकारों के लिये स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 16,347 करोड़ रूपये का बड़ा करार किया था। परंपरा के अनुसार उन्होंने आम सभा बैठक बुलाने की भी जहमत नहीं उठायी।'

पता चला है कि ई-कामर्स मेजर एमजंक्शन इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभालेगा जो विभिन्न स्पेक्ट्रम में ई-नीलामी आयोजित कराता है। गुस्साये अधिकारी ने आरोप लगाया, 'अब ई-नीलामी के लिये एमजंक्शन को रखने की प्रक्रिया क्या थी, इसकी भी जानकारी नहीं है। वैसे भी सीओए को कुछ सवाल पूछना भी पसंद नहीं है।' भारत के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिये बीसीसीआई के प्रसारण अधिकार इस समय स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं जो टेस्ट, वनडे और टी20 मैचों के लिये प्रत्येक मैच का 43-2 करोड़ रूपये का भुगतान करता है।

हालांकि स्टार ने लुभावनी आईपीएल के अधिकार हासिल कर लिये हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वे किसी भी वर्ग में प्रवेश करने के लिये इच्छुक हैं या नहीं। दिलचस्प बात है कि बीसीसीआई के मौजूदा समय में सबसे ताकतवर अधिकारियों (सीओए के अलावा) में से एक ई-नीलामी के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, 'उदाहरण के तौर पर अगर कंपनी ए जान जाती है कि कंपनी बी ई-नीलामी प्रक्रिया के दौरान 100 रूपये पर रूक जायेगी। तो कंपनी ए फिर 101 रूपये के लिये बोली लगायेगी। लेकिन अगर यह सीलबंद टेंडर होता तो अगर कंपनी ए 100 रूपये की बोली लगाती है तो कंपनी बी 500 रूपये की बोली लगा सकती है।'

इस अधिकारी ने कहा, 'विवो और ओप्पो के बीच भारतीय टीम की शर्ट के प्रायोजन को लेकर ऐसा ही हुआ था। दोनों एक दूसरे की बोली की राशि नहीं जान सकीं।' ओप्पो ने भारतीय टीम प्रायोजन करार 1079 करोड़ रूपये में हासिल किया था जबकि विवो ने 768 करोड़ रूपये की बोली लगायी थी।

गांगुली ने बीसीसीआई से कहा, समय की कमी के कारण लोढा सिफारिश लागू नहीं की गयी

नयी दिल्ली। बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) अध्यक्ष सौरव गांगुली और सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मधुकर वोरा ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर राज्य संघों के संविधान में संशोधन में और लोढ़ा समिति की सभी सिफारिशें लागू करने में कुछ व्यावहारिक मुश्किलों के बारे में जानकारी दी। बीसीसीआई सचिव अमिताभ चौधरी ने हाल में सभी राज्य संघों को ईमेल भेजकर संविधान में बदलाव की जानकारी मांगी थी और सूचित किया कि 13 इकाइयों ने पालन करने का और इस संबंध में हलफनामा पेश करने का फैसला किया है। इसके अनुसार गांगुली ने बीसीसीआई को लिखे पत्र में लिखा, ''मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले ही कैब की विशेष आम बैठक में सदस्यों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी कि बीसीसीआई के फैसले के संबंध में हलफनामे उच्चतम न्यायाय को संबोधित करते हुए दायर किये जायेंगे जिसमें राज्य और बीसीसीआई स्तर पर लागू करने की समस्याओं को बताया जायेगा।''

उन्होंने लिखा, ''विशेष आम बैठक में सदस्यों ने एक फैसला किया और आपने जो मुद्दे मेल में लिखे हैं, उन पर गौर करने के लिये एक और विशेष आम बैठक करनी होगी।'' गांगुली ने कहा, ''हमें पिछले हफ्ते आपकी मेल मिली और तब सदस्यों को इस नये मुद्दे के बारे में अपडेट करने के लिये एक अन्य विशेष आम बैठक बुलाने और इस पर फैसला लेने का समय नहीं था।'' गांगुली ने पत्र का अंत यह कहते हुए किया कि अभी समय की कमी को देखते हुए, ''हम आपके मेल में जिक्र की गयी धाराओं पर समयसीमा के अंदर कोई फैसला नहीं दे पायेंगे क्योंकि यह संघ के संविधान के खिलाफ है।'' वोरा ने लिखा, ''इस समय उच्चतम न्यायालय इस प्रस्तावित दस्तावेज पर आगे बढ़ाने के लिये पक्षों की तरफ से पेश हो रहे वकीलों की बात सुनने के लिये तैयार है।'' उन्होंने कहा, ''इसलिये इस समय संशोधनों से सिफारिशों तक का फैसला उच्चतम न्यायालय पर निर्भर करता है और उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस पर जिरह होगी।''

आईसीसी की गलती के बाद पाकिस्तान टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार

वेलिंगटन। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने स्पष्ट किया है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 श्रृंखला में मिली जीत के बावजूद आस्ट्रेलिया नहीं बल्कि पाकिस्तान टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर है। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने इस सप्ताह कहा था कि त्रिकोणीय श्रृंखला में अपराजेय रहने पर टीम नंबर वन रैंकिंग पर आ जायेगी । आस्ट्रेलिया ने आकलैंड में न्यूजीलैंड को 19 रन से हराकर श्रृंखला जीती। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने कल एक बयान में कहा कि आईसीसी की लिपिकीय त्रुटि के कारण गणना में गलती हुई और पाकिस्तान अभी भी रैंकिंग में शीर्ष पर है। रैंकिंग राउंड आफ करने पर आस्ट्रेलिया के 125-65 अंक थे और पाकिस्तान के 125-84 अंक यानी वह पाकिस्तान से 0-19 अंक पीछे है।

मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न नहीं दिए जाने पर उनके बेटे ने फिर दिया बड़ा बयान

अलीगढ़ (एजेंसी)।

जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय दुनिया में भारत की पहचान हॉकी और मेजर ध्यानचंद की वजह से होती थी। वह हमेशा से ही देश की प्रेरणा रहे हैं, लेकिन देश की आजादी के बाद से आज तक हॉकी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हमेशा ही उपेक्षित रहे। देश की सरकारों का ध्यान नहीं गया। उनको भारत रत्न न देना एक राजनीतिक साजिश है। यह बातें गुरुवार को अलीगढ़ आए मेजर ध्यानचंद के पुत्र और अर्जुन अवार्डी ओलंपियन अशोक ध्यानचंद ने कही। उन्होंने सभी सरकारों पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें तो बहुत पहले भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए था।

डीएस कॉलेज में बेटी बचाओ, बेटी खिलाओ, राष्ट्र गौरव बढ़ाओ के तहत महिलाओं की हॉकी प्रतियोगिता के आयोजन के लिए समिति के अन्य सदस्यों के साथ तैयारियों का जायजा लेने अलीगढ़ आए अशोक ध्यानचंद ने बताया कि मेजर ध्यानचंद को दुनिया में लगभग 55 देशों में 400 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जितना अपने खेल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध रहे हैं। उतना ही वे हिटलर की पेशकश ठुकराने की वजह से भी रहे हैं। बात 1936 की है, बर्लिन ओलंपिक खेलों के दौरान जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर जर्मनी की सेना में सबसे ऊंचे पद का प्रस्ताव दिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने उसे अपने देश भारत के लिए ठुकरा दिया।

हालांकि उन्हें 1956 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया और उनके जन्मदिन को देश में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद भी उन्हें भारत रत्न देने के लिए अब तक की सरकारों ने कोई खास प्रयास नहीं किया। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलना भी एक तरह का विवाद है। हालांकि सचिन तेंदुलकर को इसमें दोषी नहीं माना जा सकता। क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के जरिए देश का काफी नाम किया है, लेकिन सरकार को उनको भारत रत्न देने की घोषणा करने से पहले ध्यानचंद और उनके हॉकी के योगदान पर जरूर सोचना चाहिए था।

आगे कहा कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न न दिया जाना एक राजनीतिक साजिश है। क्योंकि वे किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा थे। उनको खेल रत्न दिए जाने के लिए खिलाड़ियों ने काफी आंदोलन भी किए और मांगें भी उठाईं, लेकिन किसी भी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे खेल प्रेमियों में काफी निराशा है।

बेटियों को आगे लाने के लिए किया जा रहा है हरसंभव प्रयास

उन्होंने कहा कि आज के समय में देश में पुरुषों की टीम है, लेकिन महिलाओं की टीम उतनी सक्रिय नहीं है। दूसरी ओर पूरे देश में यहीं स्थिति है कि हॉकी के खेल में कम ही बेटियां आती हैं। ऐसे में इसको बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। अलीगढ़ में अक्टूबर में पूरे देश से महिला खिलाड़ियों की टीमों को बुलाया जाएगा। इससे कम से कम बेटियों का हॉकी के प्रति रुझान बढ़ेगा और वे आगे आएं। वहीं ऐसे आयोजन भी समय-समय पर हर जगह कराए जाते रहेंगे।

सूरत। लंबे हनुमान रोड स्थित एफिल टॉवर के समीप के.प्रकाश ज्वेलर्स ने मालिकाना हक़ के बाद सड़क की जगह पर सीढ़ियों का निर्माण कर दिया गया था। करीब चार फिट से ज्यादा जगह सड़क पीडब्लूडी विभाग के हिस्से की है। अनेक बार अपार्टमेंट को सूचित करने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर आज पालिका ने डिमोलिशन करना शुरू किया। अपार्टमेंट और के.प्रकाश ज्वेलर्स के नौकरशाह ने हल्लाबोल खड़ा किया ,जिसके कारण स्थानीय वराछा पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ घटना स्थल पर पहुंचा। उसके बाद सीढ़ियों का महानगरपालिका के स्टॉफ ने जेसीबी मशीन द्वारा डिमोलिशन किया।

रन फॉर न्यु इंडिया मैराथन की समीक्षा बैठक

संवाददाता, सूरत। कल 25 फरवरी को सायं 6:50 बजे सूरत एअर पोर्ट पर उतरकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 7:00 बजे सूरत शहर के लालभाई कन्ट्रेक्टर क्रिकेट स्टेडियम में रन फॉर इंडिया मैराथन को प्रस्थान कराएंगे और रात 8:1 बे सूरत एयर पोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे जिसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अग्रसचिव एवं सूरत जिला प्रभारी सचिव मल दयानी की अध्यक्षता में शुक्रार को विविध विभागों के कामकाज की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

नहर में मिली किशोरी की लाश, दुष्कर्म किए जाने की आशंका

संवाददाता, सूरत। शहर के अंतिम छोर पर स्थित खरवासा क्षेत्र से गुजरने वाली नहर में एक किशोरी की लाश मिलने से सनसनी मच गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। डाक्टरों की प्राथमिक जांच में किशोरी के साथ कुछ गलत होने की आशंका की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार चलथाण से इकलेरा जाने वाली खरवासा नहर में से एक करीब 12 वर्षीय किशोरी की लाश स्थानीय लोगों ने देखा और पुलिस को सूचित किया। इसके बाद सचिन पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दी। बहरहाल किशोरी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

शोरूम में हिस्सेदार के लाखों डकार गए पार्टनर

संवाददाता, सूरत। शहर के पांडेसरा में हिस्सेदारी में शो रूम खोलने के बाद आरोपी ने हिस्सेदार को बगैर कुछ बताए ही शो रूम में रखे गए करीब 75 लाख का माल तथा निवेश किए गए रुपए सहित कुल 10.62 लाख रु. हड़प कर गए जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात हाउसिंग बोर्ड, जलाराम सोसाइटी में रहने वाले शैतानसिंह रतनसिंह राठौड ने जलाराम सोसाइटी प्लॉट नं. 132, 133 राज कमल शो रूम के नाम से श्यामलाल कपूरजी गहलोत के साथ हिस्सेदारी पर धंधा शुरू किए थे। इसी बीच ही हिस्सेदार श्यामलाल ने गत 22 फरवरी को शिकायतकर्ता शैतानसिंह को कुछ बताए बगैर ही दुकान में से करीब 75 लाख का माल रख लिया। इस तरह शैतानसिंह द्वारा धंधा में निवेश किए गए रुपए कुल 18,62,000 रुपए की ठगी व विश्वासघात किया। घटना के संदर्भ में पांडेसरा पुलिस श्यामलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच कर रही है।

इन्कटेक्स के निकट पुल का निर्माण काम चल रहा है।

बेरोजगारी से त्रस्त होकर लगाई फांसी

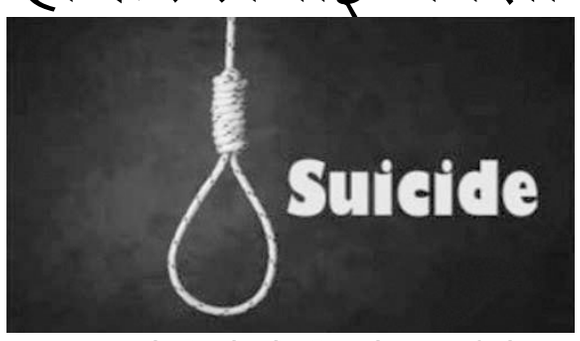

सूरत। शहर के पिपलोद क्षेत्र स्थित लेकव्यु गार्डन के पास रहने वाला एक व्यक्ति बेरोजगारी से परेशान होकर चलथाण वेसू के पास आम के पेड़ के साथ रस्सी बांधकर फांसी लगा लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपलोद के लेकव्यु गार्डन के पास घर नं. 72 में रहने वाले नानूभाई खुमानभाई राठौड (47 वर्ष) पिछले काफी समय से बेरोजगार होने के चलते तनाव में रहते थे। नानूभाई ने गुरुवार को वेसू स्थित जमनाबा पार्क के पास हिमांशु कीका की वाड़ी में आम के पेड़ में दुपट्टा बांधकर फांसी लगा आत्महत्या कर लिया। घटना के संदर्भ में खटोदरा पुलिस आत्महत्या का मामला दर्ज करके जांच कर रही है।

एसिड पीने से वराछा की महिला ने तोड़ा दम

संवाददाता, सूरत। वराछा की वर्षा सोसाइटी में रहने वाली महिला ने किसी कारणों से एसिड पी ली थी। जिसको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। जहां पर इलाज के दैरान उसकी मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वराछा क्षेत्र की वर्षा सोसाइटी घर नं. 235 में रहने वाले कालूभाई जिंजाण की पत्नी पार्वतीबेन (45वर्ष) ने गुरुवार को अपने घर में किसी कारणों से एसिड पी ली थीं। जिनको इलाज के लिए आयुष अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां पर इलाज के दौरान पार्वतीबेन की शुक्रवार को सुबह 10 बजे मौत हो गई।

विरोधियों के अनेक षड्यंत्रों के बावजूद विकास की राह पर अग्रसर है गुजरात: मुख्यमंत्री

सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में मुख्यमंत्री का जोशीला और संवेदनशील वक्तव्य

अहमदबाद। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में कहा कि लोगों ने फिर से भरोसा जताते हुए इस सरकार को रिपीट करते हुए स्पष्ट जनादेश दिया है, यही भाजपा की जनस्वीकृति को प्रतिपादित करता है।

सदन के नेता के तौर पर धन्यवाद प्रस्ताव का समापन करते हुए रूपाणी ने कहा कि संसदीय प्रणाली में विपक्ष के जनकेन्द्रित उचित सुझावों का स्वीकार करने में हम कभी नहीं हिचकेंगे। उन्होंने कहा कि विकास, प्रगति, सुख-समृद्धि और सलामती गुजरात के लोगों की मानसिकता मंष स्वीकृत हो गए हैं। विपक्ष के आरोपों के जवाब में 'भूल से भी मुख में जाति-पंथ की न बात हो' गीत की पंक्ति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार तुष्टिकरण की राजनीति और वादे करने वाली सरकार नहीं है। माननीय राज्यपाल ने उनके अभिभाषण में सरकार के जनसेवा के अनेक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख कर उसकी सराहना की, इसके लिए मैं माननीय राज्यपाल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। संसदीय प्रणालियों में सरकार और विपक्ष द्वारा की जाने वाली चर्चाओं का अनूठा महत्व होता है। प्रशंसा और आलोचना हरेक बात में होती है, लेकिन चर्चा के अंत में सच क्या है और जनहित की ठोस बात क्या है, इसी का महत्व होता है। जनहित से जुड़े उचित सुझावों होंगे तो उन्हें स्वीकारने से हम हिचकेंगे नहीं। पूर्व में आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर मूल्यांकन करने के मापदंड उपलब्ध नहीं थे। आज कंप्यूटराइज्ड युग में राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा अलग-अलग पैरामीटर्स के आधार पर विभिन्न सरकारों द्वारा होने वाले कामकाज का आंकलन कर राज्यों के विकास और जनकल्याण से संबंधित बातों का सटीक मूल्यांकन किया जाता है। मूडीज, एसएंडपी और वर्ल्ड बैंक आदि संस्थाओं की रिपोर्टों की चर्चा पूरे विश्व में होती है। उल्लेखनीय है कि मूडीज ने भारत की रेटिंग बढ़ाई है। सटीक आंकड़ों और मापदंडों पर आधारित एवं सच पर आधारित जानकारी देने को मैं उपस्थित हुआ हूं... लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार के कामकाज का मूल्यांकन चुनाव से तय होता है। गुजरात की जनता ने लगातार २२ वर्ष पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी को ४९.१ फीसदी वोट देकर संपूर्ण भरोसा जताया है। २०१२ के विधानसभा चुनावों में भाजपा का वोट शेयर ४७.८५ फीसदी था, वर्ष २०१७ में यह बढ़कर ४९.१ फीसदी हो गया है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस

राज्य में जलसंकट: नर्मदा बांध के जलस्तर में लगातार गिरावट

अहमदाबाद। राज्य में जलसंकट गहारा रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध के जलस्तर लगातार गिरावट आ रही है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध के जलस्तर में गिरावट आ रही है। नर्मदा बांध का जलस्तर घटकर 110 मीटर पर पहुंच चुका है। 1 दिन में बांध के जलस्तर में 25 सेमी की गिरावट आई है। आईबीपीटी टन में लगातार छोड़े जा रहे पानी में कटौती की जा रही है।

हाल आईबीपीटी टनल में से 9242 क्युसेक पानी छोड़ा जा रहा है। महत्वपूर्ण है कि कल 5100 पानी छोड़ा गया था। आज उसमें बढोत्तरी की गई है। नर्मदा नहर में 8329 क्युसेक पानी छोडा जा रहा है और गोडबोले गेट से 618 क्युसेक पानी छोडा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से सरदार सरोवर बांध के जलस्तर में गिरावट आ रही है।

कलक्टर ऑफिस के निकट कुहा करभा के निकट स्थित मंदिर के संत द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया। जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

4684 आदिवासी महिलाओं को दुधारू पशु देकर आत्मनिर्भर बनाया : गणपत वसावा

गांधीनगर। सूरत, पंचमहल और छोटाउदेपुर जिले की आदिवासी महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुधारू पशु दिए गए हैं। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के वर्ष में तीन जिलों की कुल 4684 लाभार्थी महिलाओं को दुधारू पशु देकर आत्मनिर्भर बनाया गया है। सूरत उत्तर के विधायक कांतिभाई बल्लर, कालोल की विधायक सुमनबेन चौहाण और संखेडा के विधायक अभेसिंह तड़वी के प्रश्न का लिखित प्रत्युत्तर देते हुए राज्य के आदिजाति विकास मंत्री गणपत वसावा ने बताया कि आदिवासी महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए दुधारू पशु देने की योजना लागू है।

पीएम मोदी आज दीव और दमण में हवाई सेवा का प्रारंभ करवाएंगे

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी फरवरी को दीव से अहमदाबाद प्लेन और दीव से दमण के बीच हेलीकॉप्टर सेवा का प्रारंभ करवाएंगे। इस सेवा के प्रारंभ होने की खबरों से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खासकर दीव से अहमदाबाद आनेवाले व्यापारियों को इस फैसले ने काफी राहत पहुंचाई है। हवाई सेवा शुरू होने से दीव, दमण और सोमनाथ की ओर जानेवाले यात्रियों में खुशी छा गई है। क्योंकि अब वे कम समय में यात्रा कर सकेंगे। हवाई सेवा शुरू होने खबरों से सोमनाथ, जूनागढ और अमरेली के लोगों में खुशी का माहौल है। प्लेन और हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से दीव से अहमदाबाद जाने के लिए अब स्थानीय लोग 8 घंटों की बस यात्रा से मुक्ति मिलेगी और केवल एक घंटे में दीव से अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक उन्हें प्लबरिंग का सामान लेने के लिए बार बार अहमदाबाद जाना पड़ता है।

गुजरात में कृषि उत्पादन में १० गुना बढ़ोतरी हो चुकी

अहमदाबाद,२३फरवरी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने आज विधानसभा में राज्यपाल के प्रवचन पर के अभिवादन प्रस्ताव में गुजरात सरकार की सफलताओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात के लोगों ने फिर एक बार विश्वास रखकर सरकार को मौका दिया है। बीजेपी को लोग पसंद कर रहे है। उन्होंने बताया कि विकास, प्रगति, सुख, सुरक्षा के लिए लोगों ने विश्वास जताया है। उन्होंने यह भी कहा बेरोजगारी भत्ता देकर बेरोजगारी की फौज नही बल्कि रोजगार के अवसर देकर हम युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ रहे है। उन्होंने कहा कि विरोध पक्ष की प्रजालक्षी सलाह को भी स्विकार किया जाएगा। हम वचनो में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास करते है। उन्होंने कहा कि सातवे वेतन की सिफारिशे सबसे पहले गुजरात राज्य में लोगु की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार देश के मुख्य राज्यो में ५९४७ करोड़ की महसुली आवक में सरप्लस के साथ गुजरात सबसे आगे है। गुजरात में कृषि उत्पादन साल १९९५-९६ में १३४९२ करोड़ था जो आज बढ़कर साल २०१६-१७ में १३७००० करोड़ तक पहुंच गया है।

जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस पार्टी की ऑफिस पर जश्न मनाया गया।

महिला नगरपार्षद के पति 5 लाख की रिश्वत लेते धरे गए

सुरत। एन्टी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने भाजपा के महिला नगरपार्षद के पति को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। भाजपा ने इस मामले में कड़े कदम उठाते हुए पति-पत्नी को सस्पेन्ड कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सुरत महानगपालिका के वोर्ड नंबर 25 गोडादरा क्षेत्र के नगरपार्षद मीनाबेन के पति दिनेशभाई राठोड को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। नगरपार्षद के पति ने शिकायतकर्ता के मकान का डिमोलीशन करवाया था। उसके बाद फिर से मकान बनाने के लिए मंजूरी देने और डिमोलिशन नहीं करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। एसीबी के अधिकारियों ने जाल बिछाकर दिनेशभाई राठोड को पांच लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **Tc.No. : GUJHIN00722**, E-mail: krantisamay@gmail.com